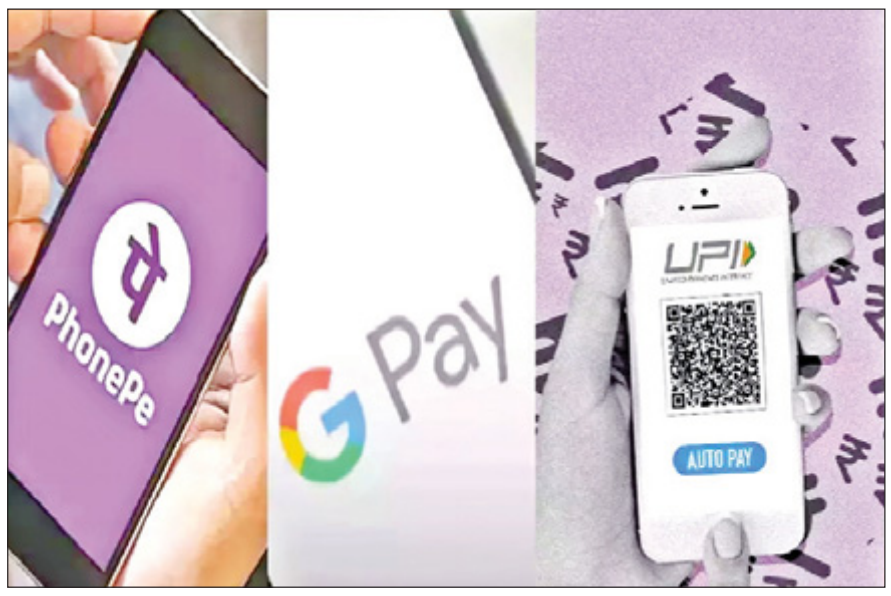
नईदुनिया



त्योहारी सीजन में यूपीआई का धमाका : अक्तूबर में 31.53 लाख करोड़ रुपये पहुंचा लेनदेन, कितनी हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली

देश में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) के जरिए होने वाले लेनदेन में त्योहारी सीजन के दौरान अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन आफ इंडिया की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक, अक्तूबर में यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 25.47 अरब हो गई। वहीं, इस दौरान लेनदेन की कुल रकम 16 प्रतिशत बढ़कर 31.53 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गई।

अक्तूबर में हर दिन औसतन करोड़ लेनदेन हुए - अक्तूबर में यूपीआई के जरिए हर दिन औसतन करीब 82.2 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। इस दौरान रोजाना लेनदेन की औसत रकम करीब 1,01,707 करोड़ रुपये रही। इससे पहले सितंबर में यूपीआई ट्रांजेक्शन की संख्या सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 24.07 अरब रही थी, जबकि लेनदेन की कुल रकम 18 प्रतिशत बढ़कर 29.37 लाख करोड़ रुपये हो गई थी।

इसके अलावा, अक्तूबर में तत्काल फंड ट्रांसफर की सुविधा देने वाली आईएमपीएस के जरिए लेनदेन की रकम सालाना आधार पर 19 प्रतिशत बढ़कर 7.63 लाख करोड़ रुपये हो गई।

एनपीसीआई के आंकड़ों के मुताबिक, पिछले महीने आईएमपीएस के जरिए रोजाना औसतन 1.21 करोड़ ट्रांजेक्शन हुए। वहीं, हर दिन लेनदेन की औसत रकम 24,601 करोड़ रुपये रही।

एमडीआर लागू करने का फैसला दिवाली तक टाला गया - एनपीसीआई ने पिछले महीने चुनिंदा यूपीआई मर्चेंट ट्रांजेक्शन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) लागू करने का फैसला दिवाली के बाद तक टाल दिया था।

इससे त्योहारी सीजन के दौरान कारोबारियों और ग्राहकों को अस्थायी राहत मिली। एनपीसीआई ने कहा था कि यूपीआई और सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए इसे लागू करने की तारीख आगे बढ़ाने का फैसला किया है।

एमडीआर का नया नियम पहले 15 अक्तूबर से लागू होना था। एनपीसीआई ने यह भी कहा कि इसे लागू करने की नई तारीख की जानकारी अलग से दी जाएगी। प्रस्तावित एमडीआर व्यवस्था के तहत रेलवे, टेलीकाम सेवाओं, बीमा और ईंधन की खरीदारी जैसी चुनिंदा मर्चेंट कैटेगरी में 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेनदेन पर 5 रुपये का तय शुल्क लगेगा। वहीं, इसी सीमा से अधिक के भुगतान बड़े कारोबारियों को करने पर 0.4 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। हालांकि, यह शुल्क प्रति ट्रांजेक्शन अधिकतम 300 रुपये तक सीमित रहेगा।

एनपीसीआई का कहना है कि एमडीआर की नई व्यवस्था का यूपीआई के व्यापक नेटवर्क पर सीमित असर पड़ेगा। अनुमानों के मुताबिक, मर्चेंट ट्रांजेक्शन में से केवल करीब 4 प्रतिशत ही नई व्यवस्था के दायरे में आएंगे। वहीं, कारोबारियों को किए जाने वाले 95 प्रतिशत से अधिक यूपीआई भुगतान पर एमडीआर शुल्क नहीं लगेगा।

न्यूज ब्रीफ

अलास्का एयर ग्रुप में 200 कर्मचारियों की छंटनी:इस साल 700 मिलियन डालर का नुकसान संभव, फ्यूल की बढ़ती कीमतों से बिगड़ी कंपनी की हालत



नई दिल्ली। अलास्का एयर ग्रुप ने घटते मुनाफे और बढ़ते खर्चों के बीच नान-कान्ट्रैक्ट स्तर के लगभग 200 कर्मचारियों की छंटनी का ऐलान किया है। कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव आफिसर बेन मिनिकुची ने कहा कि अगर यही परिस्थितियां बनी रहीं, तो एयरलाइन को इस साल 700 मिलियन डालर तक का नुकसान हो सकता है। CEO बेन मिनिकुची ने कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में बताया कि मौजूदा वित्तीय संकट यदि जारी रहता है, तो महामारी के दौर को छोड़कर वर्ष 2003 के बाद यह कंपनी का पहला एडजस्टेड प्री-टैक्स घाटा होगा। एविऐशन सेक्टर में फ्यूल की बढ़ती कीमतें और दुनियाभर में तनाव के बीच चुनौतियां कंपनी के फाइनेंशियल बैलेंस को सीधे प्रभावित कर रही है।

वर्कफोर्स के 1% से भी कम पर असर

कंपनी के स्पोक्सपर्सन के अनुसार, इस छंटनी से कुल 32,500 वर्कफोर्स के 1% से भी कम कर्मचारी प्रभावित होंगे। हटाए जाने वाले पदों में वाशिंगटन राज्य से 125 और हवाई से 48 पद शामिल हैं। एयरलाइन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी फ्रंटलाइन या नान-मैनेजमेंट कर्मचारी की नौकरी नहीं जाएगी।

वेस्ट एशिया संकट के बीच रिलायंस का बड़ा दांव, यूरोप और अफ्रीका में ईंधन निर्यात 50% बढ़ा, रेकार्ड मुनाफे की ओर कदम



नई दिल्ली। वेस्ट एशिया में संघर्ष के कारण दुनिया के कई देशों में ईंधन की सप्लाई प्रभावित हुई है। इसका फायदा उठाते हुए मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज ने अफ्रीका और यूरोप के बाजारों में पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन का निर्यात बढ़ाया है। कंपनी ने अपने ईंधन निर्यात का रुख पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, भूमध्यसागरीय देशों और यूरोप के दूसरे बाजारों की ओर किया है। इससे इन बाजारों में कंपनी की हिस्सेदारी करीब 50% बढ़ गई है। रिलायंस की सितंबर तिमाही की वित्तीय रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी ने आस्ट्रेलिया, केन्या और तंजानिया में प्रीमियम पेट्रोल की सप्लाई के नए मौके तलाशे। वहीं, भूमध्यसागरीय देशों में डीजल और विमान ईंधन (एटीएफ) की सप्लाई बढ़ाई। कंपनी ने पहली बार दक्षिण अफ्रीका को कम सल्फर वाला विमान ईंधन भी भेजा है। इससे वहां भविष्य में निर्यात की नई संभावनाएं खुली हैं। ईंधन की सप्लाई घटने से बढ़े दाम और मुनाफा वेस्ट एशिया में संघर्ष के कारण तेल और ईंधन की सप्लाई चेन प्रभावित हुई है। रूस और वेस्ट एशिया की कुछ रिफाइनरियों की क्षमता भी संघर्ष के कारण प्रभावित हुई है।

90s में छा गई थी रफ एंड टफ, अक्षय कुमार का चला जादू, गली-मोहल्लों के टेलर्स ने घर-घर पहुंचा दिया



नई दिल्ली। 90 का दशक। भारतीय फैशन के लिए यह दौर बेहद खास था। देश में उदारीकरण की बहार थी। सैटेलाइट टेलीविजन के रास्ते पश्चिमी संस्कृति तेजी से पैर पसार रही थी। तब जींस पहनना सिर्फ बड़े शहरों के संभ्रांत वर्ग तक सीमित था। उसी समय रफ एंड टफ नाम के एक स्वदेशी ब्रांड ने आम भारतीय युवाओं के बीच डेनिम को नया क्रेज बना दिया। अभिनेता अक्षय कुमार के दमदार विज्ञापनों ने इसे प्रमोट किया। गली-मोहल्ले के टेलर्स से सिलवाने वाले अनोखे रेडी-टू-स्टिच किट कान्सेप्ट ने इस ब्रांड को हर घर की पसंद बना दिया। इसकी नींव रखने वाले थे दिग्गज उद्योगपति कस्तूरभाई लालभाई। उनका और अरविंद मिल्स का इतिहास महात्मा गांधी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इसने भारत के कपड़ा उद्योग को ग्लोबल स्तर पर नई पहचान दी। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा है इतिहास रफ एंड टफ जींस और देश के सबसे बड़े टेक्सटाइल समूह अरविंद लिमिटेड का इतिहास भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वदेशी आंदोलन से जुड़ा हुआ है। महात्मा गांधी के स्वदेशी आह्वान से प्रेरित होकर लालभाई परिवार ने साल 1931 में अरविंद मिल्स की स्थापना की थी।

हो रहे बड़े बदलाव : सिलिंडर हुआ महंगा, टोल प्लाजा से लेकर म्यूचुअल फंड तक के बदल जाएंगे ये नियम

नई दिल्ली।

नवंबर महीने से कई जरूरी बदलाव लागू हो गए हैं। महीने के पहले दिन ही एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। वहीं बैंकिंग, टोल से लेकर रोजमर्रा के कई कामों में बदलाव होने वाला है, जो आपको सीधे तौर पर प्रभावित करेगा।

एलपीजी की कीमतें बढ़ीं - दिवाली और छठ पूजा से पहले देश के कारोबारियों को महंगाई का एक और झटका लगा है। सरकारी तेल विपणन कंपनियों ने एक नवंबर से 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। अलग-अलग शहरों में सिलिंडर के दाम 10 से 12 रुपये तक बढ़े हैं। हालांकि, घरेलू रसोई गैस उपभोक्ताओं को फिलहाल राहत मिली है। 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलिंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलिंडर की कीमतों में यह बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है, जब बाजारों में त्योहारों की खरीदारी तेज होने वाली है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबों और कैटरिंग कारोबार में इस्तेमाल होने वाले इन सिलिंडरों के महंगे होने से कारोबारियों की परिचालन लागत बढ़ सकती है।

पेंशन : डिजिटल प्रमाणपत्र अभियान - देशभर में डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान शुरू हो गया है। पेंशनर घर बैठे ही स्मार्टफोन से चेहरा स्कैन कर जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकेंगे। वहीं, पेंशन न रुके, इसके लिए 80 वर्ष से कम उम्र के पेंशनर 30 नवंबर तक जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड : अब डायरेक्ट प्लान डिफाल्ट - एसेट मैनेजमेंट कंपनियों के डिजिटल मंच पर म्यूचुअल फंड का डायरेक्ट प्लान डिफाल्ट होगा। अगर निवेशक रेगुलर प्लान चुनता है, तो उसे पहले इसके ज्यादा एक्सपेंस रेश्यो के बारे में बताया जाएगा। यानी निवेशक को रेगुलर व डायरेक्ट प्लान के खर्च का 7 फर्क समझने का मौका मिलेगा।

टोल प्लाजा : 1,500 रुपये का रियायती पास - रुपये में रियायती पास केंद्र सरकार ने टोल प्लाजा से 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले पात्र निजी वाहन मलिकों के लिए रियायती स्थानीय पास की व्यवस्था शुरू की है। अब सालाना 1500 से 3000 रुपये खर्च कर पूरे वर्ष संबंधित टोल प्लाजा से आवागमन किया जा सकेगा।



जीएसटी : व्यापारियों के लिए कई राहत - जीएसटी व्यवस्था में व्यापारियों को राहत देने के लिए कई बदलाव लागू किए गए हैं। इससे कारोबारियों को बिक्री के बाद छूट देने, क्रेडिट नोट जारी करने, आईटीसी रिफंड प्रक्रिया में तेजी लाने और ई-कामर्स कारोबार के लिए दूसरे राज्यों में पंजीकरण में सहूलियत मिलेगी।

कालर मोबाइल पर दिखेगा असली नाम - एक नवंबर से कालिंग नेम प्रेजेंटेशन नियम लागू हो गया है। अब अनजान नंबर से काल आने पर स्क्रीन पर सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि कालर का असली नाम भी दिखाई देगा। इसके लिए मोबाइल फोन में सेटिंग बदलने या कोई एप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी।

एटीएफ की कीमत में इजाफा - एटीएफ (विमानों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन) की कीमत 137.12 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 138.50 रुपये प्रति लीटर कर दी गई है। जेट ईंधन की कीमतों में लगातार चौथे महीने बढ़ोतरी हुई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल और ईंधन की कीमतों में तेजी के चलते यह फैसला लिया गया है। इससे पहले 1 अक्टूबर को एटीएफ की कीमत में 16 रुपये प्रति लीटर की बड़ी बढ़ोतरी की गई थी। वहीं, 1 सितंबर को 6.28 रुपये और 1 अगस्त को 5 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि हुई थी। एयरलाइंस के कुल परिचालन खर्च में जेट ईंधन की हिस्सेदारी करीब 40 फीसदी तक होती है। ऐसे में इसकी कीमत बढ़ने से विमानन कंपनियों का खर्च और बढ़ जाएगा।

चांदी इस हफ्ते 13 हजार रुपए सस्ती, 1.81 लाख आई:सोना 1576 गिरकर 1.40 लाख पर आया



नई दिल्ली

सोने-चांदी के दाम में इस हफ्ते गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी की कीमत में 13,071 रुपए की बड़ी गिरावट आई है, जिससे 1 किलो चांदी 1.94 लाख रुपए से घटकर 1.81 लाख रुपए पर आ गई है।

वहीं, सोना भी 1,576 रुपए सस्ता हुआ है। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने की कीमत 1.41 लाख रुपए से गिरकर 1.40 लाख रुपए पर पहुंच गई है।

डालर मजबूत होने से चांदी इस महीने 39,485 गिरी - चांदी इस महीने 39,485 रुपए और सोना 8,084 रुपए सस्ता हुआ है। इससे पहले 1 अक्टूबर 2026 को एक किलो चांदी के दाम 2.20 लाख रुपए और 10 ग्राम सोना 1.48 लाख रुपए पर थे। सोना-चांदी की कीमत में गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में डालर मजबूत होने और बड़े निवेशकों के ऊंचे दामों पर बिकवाली करने से हो रही है।

सोना सस्ता होने की वजहें

ऊंचे भाव पर बिक्री: त्योहारों से पहले सोना काफी महंगा हो गया था, इसलिए बड़े निवेशकों ने मुनाफा कमाने के लिए अपना सोना बेचना शुरू कर दिया।

मजबूत डालर का असर: अंतरराष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी डालर और बान्ड मजबूत हुए, जिससे ग्लोबल मार्केट में सोने की कीमतें नीचे आ गईं।

खरीदारों का हाथ खींचना: रिकार्ड महंगे दाम देखकर आम खरीदारों ने दुकानों से फिलहाल सोने की खरीदारी कम की है।

चांदी सस्ती होने की वजहें

फैक्टरियों से कम मांग: चांदी का बड़ा इस्तेमाल सोलर और इलेक्ट्रानिक्स फैक्टरियों में होता है। वैश्विक मंदी के कारण उद्योगों में इसकी मांग घटी है।

बाजार में बिकवाली का दबाव: शेयर और वायदा बाजार के उतार-चढ़ाव में बड़े ट्रेडर्स ने अचानक अपनी चांदी बेच दी, जिससे भाव तेजी से गिरे।

सोने की देखा-देखी: सर्राफा बाजार में सोना और चांदी एक-दूसरे के पीछे चलते हैं। सोने के भाव गिरते ही चांदी में भी बिकवाली शुरू हो गई।

क्या यह गिरावट लंबी चलेगी

कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया मानते हैं कि सोने-चांदी की खरीदारी किश्तों में करें। कुछ अभी खरीद लें और कुछ-कुछ 15-20 दिन के अंतराल पर। निवेश के लिए एक-दो महीने के बजाय 6 महीने से लेकर एक साल तक का सोच कर खरीदारी करें।

करोड़ों की कार बनी जी का जंजाल



नई दिल्ली। मशहूर उद्योगपति और रेमंड ग्रुप के प्रमुख गौतम सिंघानिया ने इटली की आटोमोबाइल दिग्गज मासेराती की बखिया उधेड़ दी है। इससे लक्जरी और सुपरकार सेगमेंट में हलचल मच गई। इन कारों को रईस अपने बेड़े में रखने का सपना देखते हैं। यह सबकुछ ऐसे समय में हुआ है जब मासेराती भारत में नए माडल लान्च करने को तैयार है। साथ ही अपनी डीलरशिप का विस्तार करने के साथ बड़े स्तर पर दोबारा शुरुआत करने का प्लान बना चुकी है। सिंघानिया के तीखे बयानों ने कंपनी की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस इतालवी कंपनी की कारें करोड़ों में आती हैं। रेमंड ग्रुप के चेयरमैन गौतम सिंघानिया ने सोशल मीडिया पर इतालवी लक्जरी कंपनी के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने संभावित भारतीय ग्राहकों को मासेराती की गाड़ियां खरीदने से पहले दो बार सोचने की सलाह दी है। कंपनी भारत में अपने पोर्टफोलियो को मजबूत करने में जुटी है। उसने मुंबई के बांद्रा कुर्ला काम्प्लेक्स में नई डीलरशिप शुरू की है। इस बीच में गौतम सिंघानिया की इस प्रतिक्रिया को बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। कड़े शब्दों में लगाया है आरोप सिंघानिया ने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि बिना पुरानी कमियों को सुधारे बाजार में दोबारा उतरना स्थानीय कार प्रेमियों का अपमान है।

मस्क बोले- रिटायरमेंट फंड की जरूरत नहीं होगी :पैसे बेमानी होंगे एक्सपर्ट्स बोले- दावा गलत निकला तो लोग सड़क पर आ जाएंगे

नई दिल्ली

दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलान मस्क का एक बार फिर दावा है कि भविष्य में रिटायरमेंट के लिए पैसे बचाना बेमानी हो जाएगा। उनके मुताबिक जरूरत की हर चीज और सुविधा इतनी ज्यादा मात्रा में बन जाएगी कि जमा पूंजी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा।

मस्क पिछले कुछ सालों से लगातार कह रहे हैं कि AI और रोबोटिक्स से चीजें बहुत तेजी से सस्ती बनेंगी। इसके बाद काम करने, सैलरी पाने और पैसे बचाने का पारंपरिक तरीका खत्म हो जाएगा। मस्क ने AI पर एक यूजर के पोस्ट का जवाब देते हुए यह बात कही।

विव ने लिखा था कि अपने हर उल्टे-सीधे खर्चे को मैं बस यही कहकर सही मान लेता हूं कि आगे चलकर तो सब भरपूर होने वाला है। अब ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से लापरवाह हो जाओ, पर हां कुछ सालों में इनमें से ज्यादातर चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।

रोबोटिक्स और स्पेस ट्रैवल से बनेगी मल्टी-प्लेनेटरी इकोनामी - मस्क ने हाल ही में अपने विजन को विस्तार से समझाते हुए कहा था कि रोबोटिक्स और स्पेस ट्रैवल में होने वाले बड़े सुधार एक मल्टी-प्लेनेटरी इकोनामी को जन्म देंगे।

उन्होंने कहा कि इस मुकाम पर पहुंचने के बाद



पारंपरिक करेंसी का कोई महत्व नहीं रहेगा। जब उत्पादन की कोई सीमा नहीं होगी, तो आर्थिक लेनदेन का तरीका पूरी तरह बदल जाएगा। जो चाहो वो मिलेगा, कोई चीज दुर्लभ नहीं होगी मस्क का मानना है कि AI एनर्जी सेक्टर और रोबोटिक्स मिलकर प्रोडक्शन कैपेसिटी को कई गुना बढ़ा देंगे। इसका नतीजा यह होगा कि दुनिया में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी।

मान लीजिए आज आपको नई कार खरीदनी है, घर बनाना है या अस्पताल में इलाज कराना है। इन सब कामों में इंसानों की मेहनत लगती है। इंजीनियरों और डाक्टरों की फीस होती है और सामान बनाने की लागत भी ज्यादा आती है। यही वजह है कि ये चीजें महंगी हैं।

अब सोचिए कि भविष्य में कार बनाने से लेकर खेती करने और इलाज तक का सारा काम AI और रोबोट्स कर रहे हैं। रोबोट्स न कभी थकते हैं और न ही सैलरी मांगते हैं। जब किसी भी सामान को बनाने का खर्चा लगभग शून्य हो जाएगा तो सब बहुत सस्ता मिलने लगेगा। बिल गेट्स बोले- अगले 20 साल उथल-पुथल भरे रहेंगे बिल गेट्स के मुताबिक AI से भविष्य में सब आसान होगा, लेकिन अगले 20 सालों का बदलाव इंसानी इतिहास का सबसे तनावपूर्ण समय साबित होगा। दफ्तरों से लेकर फैक्ट्रियों तक नौकरियां जाएंगी: टेलीकालिंग, एकाउंटिंग और सपोर्ट का काम AI छीनेगा, जबकि खेती, मकान निर्माण और सर्जरी का काम रोबोट्स संभाल लेंगे। सामान बनाने में इंसानी श्रम की जरूरत खत्म: अगर AI की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लगा, तो अर्थव्यवस्था में सामान बनाने के लिए इंसानों की मेहनत की कोई जरूरत ही नहीं बचेगी। इंसान के जीवन का मकसद प्रभावित होगा: काम सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं, बल्कि इंसान को एक मकसद देता है। AI के आने से इंसानी जीवन का यह संतुलन बिगड़ जाएगा।

बच्चों की देखभाल इंसानों के पास रहेगी: AI खाना बनाने, खेल और बच्चों की देखभाल करे, फिर भी ये काम इंसानों के लिए रिजर्व रखे जा सकते हैं ताकि जिंदगी का मजा बचा रहे।

त्योहारों के बीच जीएसटी से सरकार की बंपर कमाई: 2.31 लाख करोड़ के पार पहुंचा आंकड़ा, सालाना कितनी हुई बढ़ोतरी

नई दिल्ली

अक्तूबर में भारत का सकल वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) कलेक्शन सालाना आधार पर 22.9 प्रतिशत बढ़कर 2.31 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले साल इसी महीने में यह 1.88 लाख करोड़ रुपये था। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की ओर से जारी शुरुआती आंकड़ों के अनुसार है।

एक साल पहले क्या थे आकड़े

रिफंड को घटाने के बाद, जीएसटी राजस्व इस महीने में 25.6 प्रतिशत बढ़कर 2.03 लाख करोड़ रुपये हो गया। वहीं, अक्तूबर 2025 में यह 1.61 लाख करोड़ रुपये था। सकल कलेक्शन में इस वृद्धि को आयात से प्राप्त राजस्व में 42.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी का समर्थन मिला। आयात से प्राप्त राजस्व 72,246 करोड़ रुपये रहा, जो एक साल पहले 50,796 करोड़ रुपये था। घरेलू जीएसटी राजस्व में भी 15.8 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि दर्ज की गई और यह 1.37 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 1.59 लाख करोड़ रुपये हो गया।



घरेलू कलेक्शन के अंतर्गत, केंद्रीय जीएसटी (सीजीएसटी) 42,935 करोड़ रुपये रहा, जबकि राज्य जीएसटी (एसजीएसटी) कलेक्शन 51,340 करोड़ रुपये रहा। घरेलू लेन-देन से प्राप्त एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) कलेक्शन 64,769 करोड़ रुपये रहा।

अक्तूबर के दौरान कुल रिफंड सालाना आधार पर 6.5 प्रतिशत बढ़कर 27,934 करोड़ रुपये हो गए। घरेलू रिफंड 9.8 प्रतिशत बढ़कर 14,007 करोड़ रुपये हो गए, जबकि आयात पर रिफंड 3.4 प्रतिशत बढ़कर 13,927 करोड़ रुपये हो गए।

शुद्ध आधार पर, घरेलू जीएसटी राजस्व 16.4 प्रतिशत बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि सीमा शुल्क (कस्टम्स) से जुड़े जीएसटी संग्रह से प्राप्त शुद्ध राजस्व 56.2 प्रतिशत बढ़कर 58,319 करोड़ रुपये हो गया।

सालाना आधार पर कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई

प्रमुख राज्यों में, महाराष्ट्र ने 35,150 करोड़ रुपये का घरेलू जीएसटी राजस्व दर्ज किया, जो सालाना आधार पर 13 प्रतिशत की वृद्धि है। गुजरात का संग्रह 16 प्रतिशत बढ़कर 13,516 करोड़ रुपये हो गया, जबकि कर्नाटक में 18 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 15,922 करोड़ रुपये का संग्रह दर्ज किया गया। हरियाणा का संग्रह 17 प्रतिशत बढ़कर 11,529 करोड़ रुपये हो गया।

असम ने राज्यों के बीच सबसे बड़ी वृद्धि दर्ज की, जहां संग्रह 47 प्रतिशत बढ़कर 1,934 करोड़ रुपये हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों में 24 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कुल मिलाकर, अप्रैल-अक्तूबर 2026-27 के दौरान सकल जीएसटी संग्रह 13.2 प्रतिशत बढ़कर 14.77 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष की इसी अवधि में यह 13.05 लाख करोड़ रुपये था। सात महीने की इस अवधि के दौरान शुद्ध जीएसटी राजस्व 12.6 प्रतिशत बढ़कर 12.69 लाख करोड़ रुपये हो गया।